बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 153 ● नई दिल्ली ● बुधवार 01 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

## अब बाजार नहीं, जेम से तय होगा हर सरकारी खरीद का सौदा, देसी-विदेशी सप्लायर एक मंच पर लेंगे

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी और तेज बनाने के लिए जेम पोर्टल पर नई सुविधाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों से कहा गया है कि वे इनका पूरा उपयोग करें और खरीद जेम के जरिए ही करें। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई दो नई सुविधाओं, रेट कॉन्ट्रैक्ट (आरसी) और ग्लोबल टेंडर एनक्वायरी (जीटीई) को अपनाने का भी सुझाव दिया है। वित्त विभाग के मुताबिक, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत जिन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जेम पर है, उनकी खरीद इसी प्लेटफॉर्म से करना अनिवार्य है।

## स्मार्ट सिटी मिशन मोदी सरकार की कार्यशैली का उदाहरण, घोषणाएं बड़ी पर जवाबदेही शून्य - राहुल गांधी

नई दिल्ली ।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बड़ी घोषणाएं करना और फिर बिना किसी जवाबदेही के बढ़चढ़कर इसका प्रचार करना मोदी सरकार की कार्यशैली है। राहुल ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन इसी शैली का एक उदाहरण है।

उन्होंने लोकसभा में 19 मार्च को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न और सरकार के उत्तर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि स्मार्ट सिटी मिशन धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में कहा, कोई शहर स्मार्ट नहीं हो सकता, अगर वह अपने नागरिकों को बुनियादी गरिमा - साफ पानी, स्वच्छ हवा और सुरक्षा नहीं दे पाता। आपको मोदी सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन तो याद ही होगा, जिसके तारीफों के पुल बांधते प्रधानमंत्री थकते नहीं थे। उन्होंने कहा, अब जब यह योजना अपने समापन की ओर है तो मैंने संसद में सरकार से इसके वास्तविक परिणामों का हिसाब मांगा। और जो सच सामने आया उसे धोखे के अलावा कुछ और कह ही नहीं सकते, इस योजना का उद्देश्य कभी भी पूरे शहर का विकास करना ही नहीं था। रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश को एक आधी-अधूरी योजना को पूरे बदलाव की कहानी बनाकर बेचा गया। उन्होंने कहा, सवाल पूछे कि कैसे होते हैं स्मार्ट

सिटी, सफलता किस आधार पर तय हुई, कितने शहर सच में बदले, लोगों के जीवन में क्या ठोस बदलाव आया? तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, सिर्फ बताया गया की करीब 48,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, और 97 प्रतिशत प्रोजेक्ट पूरे बता दिए, लेकिन अगर सब पूरा है, तो आपके शहर में क्या बदला? राहुल गांधी ने दावा किया, जमीनी हकीकत अलग कहानी कहती है- दूषित पानी और खुले सीवर से मौतें हो रही हैं,गिरते पुल और धंसती सड़कें इस विफलता को और उजागर कर रही हैं।

उन्होंने कहा, यह योजना मोदी सरकार की असली कार्यशैली का उदाहरण है- घोषणाएं बड़ी, प्रचार उससे बड़ा, और जवाबदेही शून्य।

कांग्रेस नेता ने कहा, आप अपने शहर को सूची में खोजिए और खुद तय कीजिए कि क्या यह वही स्मार्ट सिटी है जिसका सपना आपको बेचा गया था? राहुल गांधी के प्रश्नों के उत्तर में आवासन एवं शहरी कार्य राय मंत्री तोखन साहू ने कहा था, स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत, केंद्र सरकार के 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन में से, मिशन के तहत चयन किए गए 100 शहर 47,458 करोड़ रुपये (शहरों के लिए कुल केंद्रीय आवंटन का 99 प्रतिशत हिस्सा) की केंद्रीय वित्तीय सहायता का दावा कर चुके हैं। एक मार्च, 2026 तक, राज्यों/संघ राय क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 46,326 करोड़ रुपये की राशि (अर्थात शहरों के लिए जारी कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता का 98 प्रतिशत) का उपयोग किया जा चुका है। उनका कहना था कि एससीएम के तहत, मिशन की शुरुआत से 1,64,811 करोड़ रुपये की कुल 8,064 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से 1,56,159 करोड़ रुपये की 7,784 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 97 प्रतिशत) पूरी की जा चुकी हैं और 8,652 करोड़ रुपये की 280 परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

## रुपये की रिकार्ड गिरावट पर कांग्रेस का तंज, पीएम मोदी को याद दिलाया उनका पुराना बयान

नई दिल्ली ।

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि रुपये के एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 का आंकड़ा पार करने के साथ ही प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी मुद्रा के मूल्य में गिरावट के साथ घट रही है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सुरजेवाला ने रुपये के गिरते मूल्य को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को याद किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब एक अमेरिकी डॉलर 54 रुपये के बराबर था, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहते थे कि रुपये के साथ-साथ प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए अब रुपये का मूल्य इतना गिर गया है कि एक अमेरिकी डॉलर 95 रुपये के बराबर हो गया है। इससे निर्यात को नुकसान हो रहा है, उद्योगों और व्यापार पर असर पड़ रहा है। क्या अब प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है? कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से स्थिति का जायजा लेने और सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया। शिवकुमार ने कहा कि रुपया गिर गया है, डॉलर बढ़ गया है। इसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है। मुझे केंद्र सरकार की नीतियों की जानकारी नहीं है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार स्थिति को नियंत्रित करे और सामान्य स्थिति बहाल करे। सोमवार को रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर 95.23 पर पहुंच गया, जो घरेलू और विदेशी मुद्रा बाजारों में तीव्र अस्थिरता को दर्शाता है। घरेलू मुद्रा में यह कमजोरी ब्रेंट क्रूड की कीमतों के 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकालने के कारण आई है। बाजार आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों (एफपीआई) ने अकेले मार्च में 1,31,122 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं, जिससे रुपये पर काफी दबाव पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 10 अप्रैल तक घरेलू बाजार में शुद्ध खुली स्थिति को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित करने के निर्देश के कारण आज रुपये में कुछ सुधार देखने को मिला और यह 93.58 पर खुला। हालांकि, जल्द ही दबाव बढ़ गया और रुपया 95 के स्तर पर पहुंच गया।

## श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित की 88वीं जयंती

नई दिल्ली।(ए.के.चौधरी) दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित की 88वीं जयंती उनके पुराने निवास स्थान पर श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके पुत्र एवं पूर्व सांसद, उनकी बहन श्रीमती रमा धवन तथा पुत्री रतिका सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीमती शीला दीक्षित के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा दिल्ली के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि शीला दीक्षित ने अपने कुशल नेतृत्व से दिल्ली को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया और राजधानी के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इस अवसर पर पूर्व दिल्ली मंत्री श्रीमती किरण वालिया, शिश पाल, विजय लोचव, प्रमुख कांग्रेस नेता जितेंद्र कोचर, वीरेंद्र कसाना, सी.पी. मित्तल, ए.के. त्रिपाठी, आदेश भारद्वाज, श्रीमती पुष्पा सतवीर, दिनेश कुमार, बृज मोहन, नाथू सिंह नंबरदार, लक्ष्मण रावत, राजीव वर्मा, महेंद्र भास्कर तथा Accredited Journalists Association के अध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी सहित अनेक प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सभी ने एक स्वर में कहा कि स्वर्गीय शीला दीक्षित का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा और उनका कार्यकाल दिल्ली के स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाएगा।

## बिना पसंदीदा अपशब्दों का प्रयोग किए 90 मिनट तक दिया भाषण, कांग्रेस का गृहमंत्री अमित शाह पर तंज

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधता। कांग्रेस ने कहा उन्होंने लोकसभा में एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने 90 मिनट तक बिना एक बार भी अपने पसंदीदा अपशब्द का इस्तेमाल किए उग्र भाषण दिया। विपक्षी दल का यह कटाक्ष गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के एक दिन बाद आया है। इसमें उन्होंने कहा था कि माओवादियों के सर्वोच्च निकाय और केंद्रीय ढांचे को लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाने के बाद देश नक्सलियों से मुक्त हो गया है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस ने उग्रवादियों की हिंसा के लंबे दौर को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया है। लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से मुक्त करने के प्रयासों पर बहस हुई। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई बार सार्वजनिक रूप से नक्सल समर्थकों के साथ देखा गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से माओवादियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वीडियो भी पोस्ट किए। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ÷कल

लोकसभा में गृह मंत्री ने चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने 90 मिनट तक जमकर भाषण दिया और एक बार भी अपने पसंदीदा अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जिसे पहले कई बार रिकॉर्ड से हटाना पड़ा था। कांग्रेस नेता रमेश ने इस महीने की शुरुआत में एक्स को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में गृह मंत्री पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में उनके की ओर से बोले गए उनके पसंदीदा शब्दों में से एक को हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष पद से ओम बिरला को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव को निचले सदन में तीखी बहस के बाद खारिज कर दिए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पर यह कटाक्ष किया गया था। बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सत्रों के दौरान अक्सर विदेश में रहते थे और जानबूझकर चर्चाओं में शामिल नहीं होते थे क्योंकि वे बोलना नहीं चाहते थे। दो दिन तक चली बहस के अंत में जब गृह मंत्री अपना भाषण समाप्त कर रहे थे, तब विपक्षी सदस्य सदन के वेल में जाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और नारे लगाने लगे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की कुछ टिप्पणियों के लिए माफी की मांग की थी, जिन्हें उन्होंने अपमानजनक बताया था। सोमवार को लोकसभा में अपने संबोधन में शाह ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश में हुए चुनाव में नक्सलियों का समर्थन स्वीकार किया था। वे माओवादी विचारधारा से ÷प्रभावित÷ रहीं थीं। उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ÷विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों के समर्थन के बिना रेड कॉरिडोर का निर्माण नहीं हो सकता था।÷ यह बहस गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नक्सली हिंसा के उन्मूलन के लिए घोषित समय सीमा से एक दिन पहले आयोजित की गई थी। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि देश में 31 मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) समाप्त हो जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सल मुक्त भारत है; कोई भी शोधकर्ता इसे स्वीकार करेगा।

## अस्पताल से डिस्चार्ज हुई सोनिया गांधी, डॉक्टरों की टीम ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन

नई दिल्ली । कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को मंगलवार सुबह दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। Systemic Infection से पूरी तरह उबरने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अस्पताल द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, सोनिया गांधी को 24 मार्च की रात करीब 10:22 बजे बुखार की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु जैसे वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चला। उन्हें एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया गया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। डॉक्टरों ने कहा है कि वह अब ठीक हैं, लेकिन घर पर भी उनका उपचार और फॉलो-अप जारी रहेगा। सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के कारण कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रमों में भी बदलाव करना पड़ा था। राहुल गांधी को अपनी 25 मार्च की केरल यात्रा रद्द करनी पड़ी थी, जहाँ उन्हें पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करना था। राहुल गांधी की अनुपस्थिति में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल जाकर चुनावी शंखनाद किया।वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी मां की देखभाल के लिए लगातार अस्पताल में मौजूद रहीं। 79 वर्षीय सोनिया गांधी के लिए इस साल यह दूसरी बार है जब उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इससे पहले 5 जनवरी को सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने से ठीक पहले सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर कड़ा राजनीतिक प्रहार किया था। उन्होंने 3 मार्च को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर केंद्र की चुप्पी को तटस्थता के बजाय जिम्मेदारी से भागना करार दिया था।

# युद्ध की विभीषिका का दंश

ईरान-इजराइल व अमेरिका के युद्ध को चलते अब एक महीना हो चुका है परन्तु इसकी विभीषिका कम नहीं हो रही है बल्कि उल्टे एक तरफ समझौता वार्ता की खबरों के चलते अमेरिका द्वारा ईरान में थल सैनिक उतारने की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। इस युद्ध से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि यह ऐसा लम्बाईन संग्राम है जिसके प्रभाव से दुनिया के अधिकांश देश व्यथित हो रहे हैं। इनमें भारत का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है क्योंकि स्वतन्त्रता से पहले 1947 तक भारत व ईरान की सीमाएं एक-दूसरे से मिलती थीं। यही वजह है कि भारत व ईरान के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रगाढ़ता है। इसके साथ ही भारत व ईरान के आर्थिक व सामाजिक सम्बन्ध भी गहराई लिये हुए रहे हैं क्योंकि ईसा से पूर्व सम्राट अशोक का शासन पाटलिपुत्र से लेकर तेहरान तक था जो कि आज ईरान की राजधानी है। अतः युद्ध के दुष्प्रभावों का जोर भारत पर होना ही था। इसे हम आज देख रहे हैं, बेशक इसके आयाम बदले हुए हैं क्योंकि ईरान के संकरे होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री रास्ते से होकर भारत की ऊर्जा सप्लाई का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आता है जिसके चलते आज भारत में ईंधन गैस की सप्लाई में कमी हो रही है लेकिन इसके बावजूद भारत की मोदी सरकार इस ईंधन गैस की किल्लत की मार आम भारतीय उपभोक्ताओं पर कम से कम डालने की कोशिशें कर रही है और ईरान भी भारत के ऊर्जा स्रोतों के वाणिज्यक जहाजों को जलडमरूमध्य मार्ग से गुजरने की इजाजत दे रहा है परन्तु यह युद्ध का केवल एक आयाम है। दूसरा आयाम यह है जिसकी वजह से इसके व्यापक होने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ईरान जिस तरह इजराइली व अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए अरब व खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी सैनिक अड्डों को निशाने पर ले रहा है उससे इस क्षेत्र में विश्व के दूसरे शक्तिशाली देशों रूस व चीन के हितों पर भी चोट पहुंच रही है। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के रुख को देख कर लगता है कि उन्हें इस युद्ध के दुष्परिणामों की चिन्ता नहीं है और वह अमेरिका को पुनः महान बनाने की अपनी रट में विकासशील व अविकसित राष्ट्रों की विकास प्रक्रिया को दरकिनार कर रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विगत 28 फरवरी को यह युद्ध तब शुरू हुआ जब जिनेवा में एक खाड़ी देश ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका व ईरान के बीच शान्ति वार्ता चल रही थी और इसका मुख्य विषय ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। अतः कहा जा सकता है कि अमेरिका ने यह युद्ध अपने सहयोगी राष्ट्र इजराइल की जिद के चलते ईरान पर थोपा है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमावली के पूर्णतः विरुद्ध है। इसी वजह से दुनिया के कुछ देश इसे असंवैधानिक भी बता रहे हैं। इस सन्दर्भ में यह तथ्य बहुत जरूरी है कि ईरान अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार सन्धि का सदस्य देश है अतः उसका पूरा परमाणु कार्यक्रम पहले से इस बारे में स्थापित परमाणु एजेंसी की निगरानी में था लेकिन हम देख रहे हैं कि गत 28 फरवरी को युद्ध शुरू करते हुए अमेरिका व इजराइल ने घोषणा की कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन करके इसका कथित आतंकवादी स्वरूप बदलना चाहते हैं। इस क्रम में इन दोनों देशों के आक्रमण के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई भी मारे गये परन्तु इसके बावजूद ईरान में सत्ता परिवर्तन होने के बजाय उनके द्वारा स्थापित धार्मिक- राजनैतिक प्रशासन तन्त्र ही मजबूत हुआ और ईरान की सत्ता पर अपेक्षाकृत कट्टर इस्लामी समझे जाने वाले तत्वों का कब्जा होता चला गया जिसकी वजह से ईरान की उदारवादी ताकतों को भारी झटका लगा और पूरा देश ईरान युद्धोन्माद के भाव से भर गया। इसलिए कहा जा सकता है कि ईरान यह लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है जिसमें हर ईरानी आपसी राजनैतिक व वैचारिक मतभेद भूल कर एक साथ आ गया है। वर्ना इससे पहले खामेनेई के जीवित रहते ही इस देश में उदारवादी ताकतें अपना सिर उठाने लगी थीं और ईरानी शहरों की सड़कों पर नारी अधिकारों को लेकर सरकार के विरुद्ध भारी प्रदर्शन भी होते रहते थे। भारत की इस मामले में स्पष्ट नीति रही है कि किसी भी देश में किस प्रकार का निजाम स्थापित हो इसका फैसला केवल उस देश की जनता ही कर सकती है। दूसरी ओर वर्तमान में जिस तरह भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान मिस्र, सऊदी अरब व तुर्की के साथ मिल कर इस्लामाबाद में इन देशों के विदेश मन्त्रियों के साथ मिल कर होर्मुज के जलडमरूमध्य मार्ग को खोलने की कोशिशों को वार्ता के माध्यम से अंजाम देना चाहता था लेकिन उनकी बैठक भी बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। क्योंकि पाकिस्तान स्वयं में एक अवैध परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है और पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलाने में उसकी महती भूमिका रही है। यह इस युद्ध की दिशाहीनता का एक और उदाहरण कहा जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के प्रमुख नगरों में राष्ट्रपति ट्रम्प की युद्ध नीति के खिलाफ जिस तरह नागरिकों के भारी प्रदर्शन हो रहे हैं उससे पता चलता है कि ट्रम्प की अपनी जनता के बीच ही लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। हालांकि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी अभी भी इस युद्ध का पूर्ण समर्थन कर रही है। इसके बावजूद अमेरिकी नागरिक प्रदर्शनों का यह नारा कि वे अपने देश में राष्ट्रपति का व्यवहार किसी राजा-महाराजा की तरह नहीं बल्कि चुने हुए लोकतान्त्रिक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। ट्रम्प के लिए चिन्ता बढ़ा सकते हैं क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा पुराना उदार व खुला लोकतन्त्र माना जाता है। इसके समानान्तर ट्रम्प शासन द्वारा ईरान में अपने थल सैनिक उतारने की अपुष्ट खबरों से ईरान भी काफी चिन्तित नजर आता है और इसकी संसद( मजलिस) के अध्यक्ष श्री मोहम्मद बाकर कुलीबफ ने कह दिया है कि यदि अमेरिका ऐसा करता है तो उनके देश की सेना न केवल उनका कफन तैयार करेगी बल्कि खाड़ी क्षेत्र में उसके मित्र राष्ट्रों को भी इसका परिणाम भुगतना होगा। पश्चिम एशिया के देशों में अमेरिका के कुल 16 सैनिक अड्डों में से 13 को ईरान निशाने पर ले चुका है जिससे यही आभास होता है कि इस युद्ध की समयावधि अमेरिका व इजराइल की इच्छा पर ही निर्भर करती है।

# क्या जख्म पर मरहम लगाएंगे बालेन?

**नेपाल** के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की बहन सुजाता शाह सेजेकन भारत के बेंगलुरु शहर में रहती हैं। चुनाव में बालेन की प्रचंड जीत के ठीक बाद उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा था कि भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं और इन्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता, जो हुआ वह एक अस्थायी दौर था, अब स्थिति सकारात्मक ही होगी, साथ में उन्होंने यह विश्वास भी जताया था कि भारत और नेपाल के रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। सुजाता की तमन्ना पूरी हो गई है।

केवल 35 साल की उम्र के रैपर गायक बालेन शाह ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है, तो क्या अब यह उम्मीद की जाए कि पिछले डेढ़ दशक में भारत और नेपाल के रिश्तों में प्रचंड तूफान के कारण जो गहरे जख्म उभर आए थे, उस पर बालेन मरहम लगाने की कोशिश करेंगे? क्या इस तरह की कोशिश में वे कामयाब हो पाएंगे? क्या वे दिली तौर पर चाहते हैं कि भारत-नेपाल के रिश्ते वैसे ही हो जाएं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के उदय के पहले थे? वे चीन के साथ कैसा संबंध रखना चाहेंगे? दुनिया की महाशक्तियों के लिए नेपाल कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण देश है, इसलिए ऐसे बहुत सारे सवाल इस समय नेपाल से लेकर पड़ोसी देशों तक पूछे जा रहे हैं, मगर नेपाल के लोगों ने उन पर गजब का भरोसा किया है। 2008 के बाद वहां गठबंधन सरकारें चलती रहीं लेकिन अब बालेन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को भारी बहुमत से जनता ने तख्त पर बिठाया है। यानी बालेन के पास शक्ति है। वे नेपाल की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में उन्होंने तेवर दिखा भी दिए हैं, जिस जेन जी आंदोलन से वे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, उस आंदोलन में सरकारी गोलियों से बहुत से नव युवा मारे गए थे। जांच के लिए गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। बालेन ने उस रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। ओली वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए और न रहते हुए भी चीन की गोद में खेलते रहे हैं। कहते हैं कि हाओ यांकी नाम की बला की खूबसूरत चीनी राजदूत ने ओली को अपनी मीठी गिरफ्त में ले रखा था। रमेश लेखक भी चीनी एजेंडे को ही लागू करते थे। यानी लेखक और ओली की गिरफ्तारी चीन के लिए अत्यंत कठोर संदेश है कि वामपंथ के नाम पर वह नेपाल को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश न करे।

चीन ने अभी तक खुले रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन उसकी नजर गिरफ्तारियों पर जरूर होगी, वैसे बालेन चीन को पहले भी झटका दे चुके हैं, जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने झापा संसदीय क्षेत्र में नेपाल-चीन फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था, मगर बालेन ने चुनाव के पहले जारी अपने घोषणा पत्र से नेपाल-चीन फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क को हटा दिया था। यह पार्क चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना का हिस्सा है। यानी बालेन संकेत दे रहे हैं कि वे चीन की गोद में नहीं बैठने वाले हैं। तो क्या यह भारत के लिए शुभ संकेत है? काफी हद तक यह माना जा सकता है लेकिन भारत को यह उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए कि वे चीन से दूर रहेंगे तो भारत की गोद में बैठ जाएंगे। उनके रवैये को लेकर दो उदाहरणों पर गौर करिए, जब वे काठमांडू के मेयर थे तब उन्होंने फिल्म आदिपुरुष पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि उस फिल्म में सीता को भारत का बताया गया था जबकि सीता की जन्मस्थली जनकपुर, नेपाल में है। इसके अलावा केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए जब एक ऐसा नक्शा जारी किया जिसमें भारत के उत्तराखंड राज्य के कुछ हिस्सों को नेपाल का दिखाया गया था तो बालेन ने न केवल समर्थन किया बल्कि नक्शा उन्होंने काठमांडू के मेयर कार्यालय में टांग लिया था, इसलिए हमें यह मान कर चलना चाहिए कि बालेन शाह वही करेंगे जो उनके नेपाली राष्ट्रवाद को और पुख्ता करेगा। वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो नेपाल के नव युवाओं को अखर जाए लेकिन यह भी ध्यान जरूर रखेंगे कि नेपाल के हित क्या हैं। नेपाल लैंड लॉक्ड है और भारत के साथ 1250 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन के साथ सीमा 1414 कि.मी. है लेकिन चीनी सीमा ऊंचे पहाड़ों और बर्फीली चोटियों वाली है। यानी भारत के साथ उसका व्यापार जितना सुगम हो सकता है, चीन के साथ नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि भारत के साथ नेपाल के सांस्कृतिक संबंध हैं। बालेन हालांकि इस बात को कभी स्पष्ट रूप से कहते नहीं हैं मगर वे मधेसी हैं। मधेसी भारतीय मूल के लोगों को कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत चीन के साथ नेपाल का कोई सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि बालेन निश्चय ही उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देखेंगे। इस उम्मीद को सम्मानपूर्ण सहयोग के रूप में यदि भारत सरकार पूर्ण कर पाए तो न केवल जख्म मिटेंगे बल्कि ताजी हवा के झोंके के साथ भारत-नेपाल के रिश्तों में मिठास की नई बयार भी उभरेगी। दोनों देशों के लिए ये संबंधों के सृजन का नया अवसर है। उम्मीद करें कि सब शुभ हो।

सम्पादकीय...

## मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने और कूटनीति को विफल बताने वालों को यह रिपोर्ट देखनी चाहिए

देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से भारत पहले अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है उस पर दबाव बढ़ने से कई तरह की अटकलें लगाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने वाले और मोदी की विदेश नीति को विफल बताने वाले विपक्षी नेताओं को यह देखना चाहिए कि जब भारत के सामने ऊर्जा संकट मंडराया तो दुनिया के कई देश मदद के लिए खड़े हो गए जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों तक भरोसे का रिश्ता बनाया था। खासकर अफ्रीकी देशों से बढ़े आयात ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने समय रहते अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाया था। आज वही रिश्ते और रणनीतिक फैसले भारत की ढाल बनकर खड़े हैं और यही असली कूटनीति की ताकत है। देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से भारत पहले अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है उस पर दबाव बढ़ने से कई तरह की अटकलें लगाई गईं। लेकिन भारत न तो घबराया और न ही संकट में फंसा। इसका कारण है मोदी सरकार की दूरदर्शी ऊर्जा नीति और समय रहते उठाए गए रणनीतिक कदम। आज स्थिति यह है कि भारत में कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की उपलब्धता एक महीने पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं है और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारु बनी हुई है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति का परिणाम है। देखा जाये तो सबसे बड़ा बदलाव आया है ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में। एक दशक पहले तक भारत केवल 27 देशों से कच्चा तेल लेता था, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। अमेरिका, रूस, कनाडा, नार्वे से लेकर अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया, अल्जीरिया और अंगोला तक भारत ने अपने ऊर्जा संबंधों का विस्तार किया है। एलएनजी के लिए कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और मोजाम्बिक जैसे नए साझेदार जुड़े हैं। यही नहीं, रणनीतिक भंडारण की दिशा में भी भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पिछले 11 वर्षों में 5.3 मिलियन टन का रणनीतिक तेल भंडार तैयार किया गया है और अतिरिक्त क्षमता पर तेजी से काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत के पास आपूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। मोदी सरकार ने केवल आपूर्ति बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि प्रबंधन को भी मजबूत किया। चौबीसों घंटे निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया और एक अंतर मंत्रालयी समूह रोज बैठक कर हालात का आकलन कर रहा है। जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए और राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

# पारा बढ़ने के साथ बढ़ता जल संकट

**जलवायु परिवर्तन के कारण अप्रत्याशित बारिश और लंबे समय तक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे जल संकट एक राष्ट्रीय आपातकाल में बदल गया है जो स्वास्थ्य, भोजन और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इस बीच, पानी की बर्बादी हर दिन जारी है, टैंक ओवरफ्लो हो रहे हैं, पाइप लीक हो रहे हैं और नल लगातार बह रहे हैं। बहुत से लोग अब भी पानी को असीमित मानते हैं, यह नहीं समझते कि आज बर्बाद की गई हर बूंद हमें कल पानी की कमी के करीब ले जाती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब बर्बादी बंद करके बचत शुरू करने का समय आ गया है। भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और पानी की कमी और भी बदतर होती जाएगी। साथ ही यह जल संकट सिर्फ इस गर्मी तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और खराब जल नीतियां हमें राष्ट्रीय आपातकाल की ओर धकेल रही हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है और पानी की कमी की समस्या भी शुरू हो गई है। बढ़ते तापमान, लंबे दिनों और अनिश्चित आपूर्ति के कारण भारत के अधिकांश शहरों और कस्बों में पानी की कमी होना लगभग तय है। कुछ ही समय में पानी की कटौती, टैंकरों पर निर्भरता और नलों का सूखा पड़ना आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा लेकिन आपको संकट के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पानी की कमी के तनाव से बचने के लिए आप अभी कुछ आसान और कारगर कदम उठा सकते हैं।इसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट हर वर्ष अधिक गंभीर होता जा रहा है।**

**गर्मियों** की शुरुआत के साथ ही देशभर में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। इससे जुड़े समाचार विभिन्न माध्यमों से प्रकाश में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 29 मार्च को 'मन की बात' में कहा कि देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। ये समय जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का है। पिछले 11 वर्षों में 'जल संचय अभियान' ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देशभर में करीब 50 लाख आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसी दिन देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी से ऐसी ही खबर आई। पेयजल संकट की समस्या लेकर जल संस्थान के दफ्तर पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं की अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। ऐसे में गुस्साए लोगों ने ईई कार्यालय पर ताला जड़ दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। प्रयागराज-मिर्जापुर राजमार्ग पर स्थित मेजा रोड बाजार में भीषण गर्मी के साथ पेयजल संकट गहरा गया है। गर्मी की तल्खी के साथ ही हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पेयजल संकट शुरू हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ-साथ पानी का उपयोग भी बढ़ जाता है। आप ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा नहाते हैं और एयर कंडीशनर, पंखे और कूलर लगातार चलाते रहते हैं लेकिन इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत असुविधा तक ही सीमित नहीं है। जितनी ज्यादा गर्मी होती है, उतना ही ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। आप ज्यादा पानी पीते हैं। आप ज्यादा बार नहाते हैं। आप कूलर और पंखे ज्यादा देर तक चलाते हैं फिर भी पानी की जरूरतें बढ़ने के बावजूद आपूर्ति इसके साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है। वास्तव में यह घट रही है। आपने शायद पहले से ही पानी से जुड़ी रोजमर्रा की चुनौतियों को महसूस किया होगा। नगर पालिका द्वारा पानी की आपूर्ति के घंटे कम होते जा रहे हैं, महंगे टैंकर के पानी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और भूजल स्तर चिंताजनक रूप से घट रहा है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार, लगभग 21 भारतीय शहरों में जल्द ही भूजल खत्म होने की आशंका है जिससे 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे। इनमें चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। जल, जिसे कभी एक निःशुल्क और असीमित संसाधन माना जाता था, अब भारत के लिए जीवन-मरण का सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। भारत में जल संकट न केवल भविष्य का खतरा है, बल्कि देश के कई हिस्सों में पहले से ही एक चुनौती बना हुआ है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों से लेकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे सूखाग्रस्त राज्यों तक, इसके संकेत हर जगह दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु के 2024 के संकट को ही लीजिए, जब पूरे महानगर में बोरवेल और झीलें सूख गईं। टैंकरों की कीमतें आसमान छू गईं जिससे हजारों लोगों को पीने और दैनिक उपयोग के लिए पानी की राशनिंग करनी पड़ी। रिपोर्ट में बताया गया कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसके चलते कई समुदायों को प्रति टैंकर 2500 रुपये तक चुकाने पड़े, जो सामान्य कीमत से लगभग दोगुना था। चेन्नई, जो 2019 में भीषण संकट के दौर से गुजरा था, आज भी गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और इस साल भी जलाशयों का जलस्तर खतरनाक रूप से कम हो गया है। दिल्ली-एनसीआर में टैंकरों पर बढ़ती निर्भरता और घटते भूजल स्तर ने लाखों लोगों के लिए पानी को एक दैनिक संघर्ष बना दिया है और इसका असर सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र भी इससे समान रूप से प्रभावित है। फसलें बर्बाद होने, बोरवेल सूखने और सिंचाई की लागत बढ़ने से किसानों को इस संकट का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कपड़ा, विनिर्माण और निर्माण जैसे जल पर निर्भर उद्योगों को भी परिचालन संबंधी जोखिमों और बढ़ती लागतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत का जल संकट रातों-रात नहीं आया। यह दशकों से पानी के अत्यधिक उपयोग, खराब योजना और निष्क्रियता का परिणाम है, जिसके चलते यह समस्या हर साल और भी गंभीर और खतरनाक रूप ले रही है। बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण, प्राकृतिक जल संसाधनों का प्रदूषण और अनियंत्रित भूजल दोहन ने भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है, जो भारत की लगभग 85 फीसदी पेयजल आपूर्ति करता है। शहर अपनी जल प्रणालियों की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से फैल रहे हैं और 2025 की शुरुआती और भीषण गर्मी ने मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर और भी बढ़ा दिया है। जल संसाधनों का बढ़ता प्रदूषण समस्या को और भी गंभीर बना देता है। गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी नदियां कचरे और रसायनों से भर रही हैं जिससे अधिक से अधिक लोग घटते भूजल या महंगी टैंकर से आने वाले पानी पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शहरी झीलें और तालाब या तो सूख गए हैं या विषैले हो गए हैं जिससे लाखों लोगों के पास सुरक्षित जल के स्रोत कम होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अप्रत्याशित बारिश और लंबे समय तक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे जल संकट एक राष्ट्रीय आपातकाल में बदल गया है जो स्वास्थ्य, भोजन और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इस बीच, पानी की बर्बादी हर दिन जारी है, टैंक ओवरफ्लो हो रहे हैं, पाइप लीक हो रहे हैं और नल लगातार बह रहे हैं। बहुत से लोग अब भी पानी को असीमित मानते हैं, यह नहीं समझते कि आज बर्बाद की गई हर बूंद हमें कल पानी की कमी के करीब ले जाती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब बर्बादी बंद करके बचत शुरू करने का समय आ गया है। भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और पानी की कमी और भी बदतर होती जाएगी। साथ ही यह जल संकट सिर्फ इस गर्मी तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और खराब जल नीतियां हमें राष्ट्रीय आपातकाल की ओर धकेल रही हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है और पानी की कमी की समस्या भी शुरू हो गई है। बढ़ते तापमान, लंबे दिनों और अनिश्चित आपूर्ति के कारण भारत के अधिकांश शहरों और कस्बों में पानी की कमी होना लगभग तय है। कुछ ही समय में पानी की कटौती, टैंकरों पर निर्भरता और नलों का सूखा पड़ना आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा लेकिन आपको संकट के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पानी की कमी के तनाव से बचने के लिए आप अभी कुछ आसान और कारगर कदम उठा सकते हैं।इसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट हर वर्ष अधिक गंभीर होता जा रहा है।

पेयजल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण को सामूहिक लक्ष्य बनाना होगा। इसमें सरकार और समाज दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। कुओं, झीलों, तालाबों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन को घरों और संस्थानों में अनिवार्य बनाया जाए, ताकि वर्षा का पानी संरक्षित होकर भूजल स्तर बढ़ा सके साथ ही पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों का पुनर्जीवन किया जाना चाहिए। शहरों में पाइपलाइन लीकेज को तुरंत ठीक कर पानी की बर्बादी रोकना भी जरूरी है। यदि सरकार और समाज मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

# माओवादी मुक्ति से शांति एवं संतुलन की नई संभावनाएं

**भारत** जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र के सामने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हमेशा से बहुआयामी रही हैं। इन चुनौतियों में नक्सलवाद या माओवादी हिंसा एक ऐसी समस्या रही, जिसने दशकों तक देश की आंतरिक शांति, विकास और सुशासन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों ने न केवल विकास को अवरुद्ध किया, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान भी ली। लेकिन आज जब बस्तर जैसे माओवादी गढ़ से 25 लाख के इनामी सरगना पापा राव का अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण करना एक निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आया है, तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत माओवादी मुक्ति की ऐतिहासिक दहलीज पर खड़ा है। नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानता, उपेक्षा और शोषण में रही हैं, लेकिन समय के साथ यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों से भटककर एक हिंसक और विध्वंसकारी विचारधारा में बदल गया। माओवादी संगठन न केवल विकास कार्यों में बाधा डालते रहे, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों को भय और हिंसा के माध्यम से नियंत्रित किया। स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे को नष्ट करना उनकी रणनीति का हिस्सा बन गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह आंदोलन अब जनहित का नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का माध्यम बन चुका है। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद/माओवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह अब लगभग अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक में 10,000 से अधिक माओवादियों के आत्मसमर्पण, सुरक्षा बलों की आक्रामक एवं रणनीतिक कार्रवाई तथा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से हुए विकास कार्यों ने माओवादी आंदोलन की जड़ों को कमजोर कर दिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में माओवादी हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। विशेष रूप से शीर्ष नेतृत्व के आत्मसमर्पण, जैसे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों के सरेंडर ने संगठन को नेतृत्वहीन कर दिया, जिससे माओवादी संरचना भीतर से कमजोर पड़ गई। इस सफलता के पीछे सरकार की बहुआयामी रणनीति रही, जिसमें केवल सैन्य-पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि विकास, पुनर्वास और प्रशासनिक पहुंच को भी समान महत्व दिया गया। रेड कॉरिडोर क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण, मोबाइल टावरों के माध्यम से 4जी नेटवर्क का विस्तार, स्कूलों और आईटीआई संस्थानों की स्थापना ने इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा। वहीं 'फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों' की रणनीति के माध्यम से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के गढ़ों में घुसकर निर्णायक कार्रवाई की। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, रोजगार और समाज में पुनर्स्थापना की व्यवस्था ने भी माओवादी कैडर को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह समन्वित रणनीति, दूरदर्शिता और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है कि देश आज नक्सलवाद के अंत के ऐतिहासिक चरण के निकट खड़ा दिखाई दे रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी और दृढ़ रणनीति अपनाई। गृहमंत्री अमित शाह की सूझबूझ और स्पष्ट दृष्टिकोण ने इस अभियान को एक नई दिशा दी। सरकार ने एक ओर जहां सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों से सशक्त किया, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं को भी गति दी। 'सुरक्षा और विकास' के इस दोहरे दृष्टिकोण ने माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए सघन अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को गहराई से कमजोर किया है। बस्तर, जो कभी माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां आज आत्मसमर्पण की घटनाएं बढ़ रही हैं। पापा राव जैसे शीर्ष माओवादी नेता का आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि माओवादी संगठन अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह केवल एक व्यक्ति का आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि एक विचारधारा के पतन का प्रतीक है। माओवादी मुक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देश के उन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता स्थापित होगी, जो लंबे समय से हिंसा की चपेट में रहे हैं। जब बंदूकें खामोश होंगी, तब विकास की आवाज बुलंद होगी। सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का संचार होगा। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय, जो अब तक भय और असुरक्षा में जी रहे थे, वे अब अपने अधिकारों और अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही, माओवादी हिंसा के समाप्त होने से भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। जब देश के भीतर शांति होगी, तब ही बाहरी खतरों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। नक्सलवाद जैसी समस्याएं अक्सर विदेशी शक्तियों और असामाजिक तत्वों के लिए भी अवसर प्रदान करती हैं, जिन्हें समाप्त करना राष्ट्रीय हित में अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से माओवादी मुक्ति न केवल आंतरिक, बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की समान पहुंच आवश्यक होती है। माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में इन सभी तत्वों का अभाव था। वहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी और लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रही थीं। लेकिन अब जब माओवादी प्रभाव घट रहा है, तब सरकार के लिए यह अवसर है कि वह इन क्षेत्रों में सुशासन की मजबूत नींव रखे। पंचायतों को सशक्त किया जाए, स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाए और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। यह भी आवश्यक है कि माओवादी विचारधारा के प्रभाव को केवल सुरक्षा उपायों से ही नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी चुनौती दी जाए। शिक्षा, जागरूकता और संवाद के माध्यम से लोगों को यह समझाना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। लोकतंत्र में परिवर्तन का मार्ग शांतिपूर्ण और संवैधानिक होता है। इस दिशा में समाज, सरकार और नागरिक संगठनों को मिलकर प्रयास करना होगा। माओवादी मुक्ति के इस दौर में यह भी ध्यान रखना होगा कि जिन कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई थी, वे दोबारा न उभरें। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और विकास की समावेशी नीति को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

आदिवासी क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों का सम्मान करते हुए विकास की योजनाएं लागू की जानी चाहिए। केवल भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जिस दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ माओवादी समस्या का समाधान किया जा रहा है, वह न केवल वर्तमान के लिए, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक है। यह दिखाता है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो, रणनीति स्पष्ट हो और कार्यान्वयन प्रभावी हो, तो कोई भी समस्या असाध्य नहीं है। निश्चिततौर पर माओवादी मुक्ति केवल एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र, विकास और सुशासन की जीत है। यह उस विश्वास का प्रतीक है कि भारत अपने आंतरिक संघर्षों को शांतिपूर्ण और निर्णायक ढंग से सुलझाने में सक्षम है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैपरहाउस एरिया, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00862)

# कुशीनगर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कान्क्लेव कुशीनगर हवाई अड्डा, बस अड्डा, रेल जंक्शन चालू किए बिना पर्यटकों के साथ धोखा, दिखावा, धन की बर्बादी का संदेश होगा-अभय रत्न बौद्ध

नई दिल्ली (आकाश शक्य )राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद बुध्दगया एवं बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के राष्ट्रीय समन्वयक एवं संगठक अभय रत्न बौद्ध ने भारत सरकार की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को -पत्र -याचिका- भेजकर कहा है कि-

1 - वर्ष 2014 से (लगातार 12 वर्षों से) भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र, जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश को गोरखपुर रेल जंक्शन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -28 के साथ ग्राम सुकरौली, जगदीशपुर, रामपुर, हाटा बाजार, अहरौली होते हुए -कुशीनगर रेल जंक्शन- बनाने एवं नई रेल लाइन बिछाने की अपील -राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद बुध्दगया- के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर आग्रह करते आ रहे है।

इस संदर्भ में वर्ष 2017-18 में रेल प्रशासन द्वारा कुशीनगर के लिए घुमाकर गोरखपुर वाया ,-पडरौना,क पथरदेवा,

ह-कुशीनगर, ह- हैतिमपुर, ख- हाटा,ख-रामपुर सोहरौना, त- बेन्चरा,ह- सरदार नगर स्टेशन बनाने का सर्वे प्लान किया गया और प्रशासन द्वारा लगभग 1345 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च की गई।

देखने में आया है कि बौद्ध पर्यटक स्थलों के साथ की जा रही भेदभाव पूर्ण नीति के चलते गोरखपुर -कुशीनगर रेल परियोजना का कार्य रोक दिया गया है। जिससे देशी- विदेशी पर्यटकों में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है।

2 - अंतरराष्ट्रीय पर्यटक केंद्र, जनपद कुशीनगर भ्रमण के लिए आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों, यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए 590 एकड़ भूमि पर कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहली बार शिलान्यास 10 अक्टूबर 1995 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बहन मायावती के कार्यकाल में केंद्रीय ममंत्री भारत सरकार ,गुलाम नबी आजाद ने किया था जिसे 20 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई।

कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 260 करोड़ से 448 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च करके हवाई जहाजों के संचालन हेतु

20 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय, नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात एक- दो पड़ोसी देशों के जहाजों के आवागमन के बाद कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भेदभावपूर्ण नीति के चलते एक -सफेद हाथी- बन कर रह गया है। जो मात्र देशी- विदेशी पर्यटकों के लिए दिखावा बन गया है। देखना होगा कि कब तक भारत सरकार एवं

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं अधिकारी गण आपसी सहमति बनाकर देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से हवाई जहाजों का आना -जाना शुरू करा पाएंगे? या फिर कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सफेद हाथी बनकर ही रह जाएगा।

3- कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के आने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में बस अड्डा का संचालन किया गया था,जो कि पुराने बस अड्डा के स्थान पर प्राइवेट बसों के लिए पार्किंग बना दिया गया है।

पर्यटक विरोधी

अफसरशाही के चलते गोरखपुर, देवरिया, कसया, तमकुही, गोपालगंज आदि शहरों से जाने - आने वाली बसें कुशीनगर पर्यटक स्थल बस अड्डा होकर गुजरती थी और पर्यटकों की यात्रा सुगम होती थी। किंतु आज अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल कुशीनगर आने-जाने के लिए कोई भी सिटी बस या रोडवेज बस अड्डा की व्यवस्था नहीं है।

कुशीनगर आने वाले पर्यटकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पहले की भांति पर्यटक स्थल कुशीनगर में सिटी बस, रोडवेज बसों के ठहराव के लिए बस अड्डा बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हमारा मानना है कि पर्यटकों को तड़पाकर बिना सुविधा प्रदान किए पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार लाखों -करोड़ों की धनराशि -इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कांक्लेव- के नाम पर खर्च करके बर्बादी का संदेश क्यों देना चाहती है? यदि सरकार कुशीनगर में निवेश चाहती है, राजस्व प्राप्त करना चाहती है तो! बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा का संचालन करने की कार्य योजना तत्काल लागू करें और यदि सरकार के मंत्री गण और अफसर शाही सच्चे मन से पर्यटकों का कल्याण करना चाहते हैं तो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, पर्याप्त टॉयलेट बाथरूम जन सुविधा परिसरों आदि विकास कार्यों का निर्माण करवा कर कुशीनगर को -स्मार्ट पर्यटक सिटी- के रूप में विकसित किये जाने की कार्य योजना बनाई जाए अन्यथा -सौ दिन चले अढ़ाई कोस- की कहावत चरितार्थ होगी और पर्यटन विकास के नाम पर पर्यटकों के साथ विश्वास घात होता रहेगा। याचिका के प्रति भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री शशि प्रकाश गोयल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

जारी कर्ता

एस.के. गौतम

केंद्रीय कार्यालय सचिव

बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत।

# अब वीर एकलव्य के नाम से जाना जाएगा बेलनहवा चौराहा

फरेंदा, महराजगंज।

विधानसभा फरेंदा क्षेत्र के निषाद बाहुल्य इलाके का बेलनहवा चौराहा अब वीर एकलव्य चौराहे के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने मंगलवार को यहां स्थापित एकलव्य की मूर्ति का अनावरण करते हुए चौराहे का नामकरण भी किया। बेलनहवा चौराहा आसपास के दर्जन भर निषाद बाहुल्य गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख चौराहा है। यहां के पूर्व प्रधान स्वर्गीय तपसी निषाद की इच्छा थी कि इस चौराहे का नाम उनके बिरादरी के वीर सपूत एकलव्य के नाम से हो।

क्षेत्र के पटवारी निषाद,राम मिलन साहनी आदि ने क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र चौधरी से इसके नामकरण की मांग की थी। विधायक वीरेंद्र चौधरी ने करीब एक लाख की लागत से वीर एकलव्य की मूर्ति बनवाकर उसकी स्थापना उक्त चौराहे पर की। मंगलवार को भव्य समारोह और भारी जनसमूह की उपस्थिति में चौराहे का नाम करण किया। जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो विधानसभा के चुनावी वर्ष में कांग्रेस विधायक का यह बड़ा राजनीतिक दांव है।

## विधायक वीरेंद्र चौधरी ने एकलव्य की मूर्ति का अनावरण कर किया चौराहे का नामकरण

जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से आप द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि आपके वोटों के बल पर अपना हित साधते रहे। कभी आपके सम्मान को तवज्जो नहीं दिया। उल्टे जल और जंगल जिस पर पहला हक आपका है,उसका दोहन करते रहे। उन्होंने कहा कि यह इलाका बाढ़ ग्रस्त है। बरसात के मौसम में यहां के लोग रात भर सो नहीं पाते थे,इस डर से कि रात बिरात बाढ़ न आ जाय और आपका सबकुछ बहा ले जाय। कहा की आप ने अवसर दिया तो सबसे पहले बाढ़ से बचाव के लिए बांधों को मजबूत करने का काम किया। कुछ काम जो अभी बाकी है,वह आने वाले एक दो महीने में शुरू होंगे। कार्यक्रम के अंत में विधायक चौधरी ने स्वर्गीय तपसी की पत्नी को अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आनंद नगर के प्रथम चेयरमैन जय प्रकाश लाल, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष झिनकू चौधरी, जिला पंचायत सदस्य सुरेश साहनी,मोहन प्यारे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश मौर्य, विजय कुमार चौधरी, डाक्टर राम नारायन चौरसिया, जिला पंचायत सदस्य राहुल शर्मा,विनय तिवारी, हनुमान प्रसाद,रामदेव यादव,शेषमणि यादव, प्रदीप गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का शानदार संचालन मुजम्मिल ने किया।

# हत्या के मुकदमे में फरार अभियुक्त के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई

भटनी देवरिया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भटनी पुलिस ने हत्या के मुकदमे में फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में थाना भटनी पुलिस ने मु.अ.सं. 67/2023 धारा 302, 498ए, 306 आईपीसी में फरार चल रहे अभियुक्त सुनील प्रसाद पुत्र स्व. बंधु प्रसाद निवासी बनकटा दीक्षित थाना भटनी जनपद देवरिया के विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मंगलवार को उसके घर पहुंचकर उद्घोषणा और मुनादी की कार्रवाई की। पुलिस ने ग्राम चौकीदार से डुग्गी पिटवाकर फरार अभियुक्त की जानकारी सार्वजनिक कराई तथा उसके घर और सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष मृत्युन्जय राय, कांस्टेबल बृजेन्द्र सिंह यादव एवं कांस्टेबल श्रीराम यादव शामिल रहे।

भटनी पुलिस ने घर पर मुनादी कर चस्पा किया नोटिस

## शीशम के पेड़ से लटका मिला महिला का शव, इलाके में सनसनी

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कौवासार स्थित सेखुई नहर के पास एक 51 वर्षीय महिला का शव शीशम के पेड़ से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान माया देवी (51 वर्ष), पत्नी निजामुद्दीन, निवासी ग्राम सभा बभनौली के रूप में हुई है। सुबह नहर किनारे पेड़ से शव लटकता देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंद्रभूषण प्रजापति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और मृत्यु के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

## समाज कल्याण प्राथमिक विद्यालय छितौनी में अंकपत्र व पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

समाज कल्याण प्राथमिक विद्यालय छितौनी में सत्र 2025-26 के अंतर्गत अंकपत्र एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया तथा अभिभावकों की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में काजल, रामू चौहान, कृष्णा जायसवाल, अनुपा चौहान, रूपाली चौहान, रीमा, पियूष, रिया, दिव्या और हिमांशु चौहान शामिल रहे। वहीं पूरे विद्यालय में सर्वाधिक 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सोनम मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिन्हें अगले सत्र की 30 प्रतिशत शुल्क माफी प्रदान की गई। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली रूपाली चौहान को 25 प्रतिशत शुल्क माफी दी गई, जबकि सर्वाधिक उपस्थिति के लिए आलोक चौधरी को भी 25 प्रतिशत शुल्क छूट से सम्मानित किया गया।

द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अन्य विद्यार्थियों में खुशबू, शिवानी, पृथ्वीराज, सत्यम, निशा, अंतिम, रजत, जय, किरण, पुष्पा एवं नंदिनी शामिल रहे, जबकि तृतीय स्थान पर मनीष, आभार, शिवानी, राजनंदन, अमृता, अनुष्का, श्यामू, नंदिनी, प्रिया एवं रूबी निषाद रहे। विद्यालय के शिक्षकों–अभय मिश्रा, ओमप्रकाश भास्कर, रामनरेश वर्मा, अनुपमा मिश्रा, पुनिता, पुष्पा, प्रियंका एवं अर्पिता–ने बच्चों को 'अटेंडेंस किंग/क्वीन', 'परफेक्ट आउटफिट', 'स्माइल डिस्ट्रीब्यूटर' और 'परफेक्ट बिहेवियर' जैसे विशेष पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। इनमें मुस्कान, अंकुश, जयदीप, सीता, कविता, सोनम, गोलू, कृष्ण, श्वेता, नीरज, प्रिया और बबीता समेत कई बच्चों को स्माइली गिफ्ट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में दिनेश गुप्ता, अजय गुप्ता, सोमेश्वर जायसवाल, राबड़ी देवी, रेखा देवी, लालमति देवी, मीरा देवी, नरेश चौहान, दिवाकर, हीरालाल, सुखई चौहान, नंदू चौहान, ज्ञानती देवी एवं हरिलाल कुशवाहा सहित सैकड़ों अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक गिरजेश मिश्रा ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों एवं उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

# अन्तिम संस्कार के दौरान डूबे व्यक्ति की मिली लाश

**सिरकोनी, जौनपुर।** जफराबाद क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के पास गोमती नदी में मंगलवार को मुरारपुर गांव के श्याम बहादुर चौहान की लाश मिली। वह सोमवार को जफराबाद के नाव घाट के पास अंतिम संस्कार बाद गोमती नदी में नहाते समय डूब गया था। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल मय फोर्स मौके पर पहुंच गये। ज्ञात हो उक्त गांव की एक वृद्धा के अंतिम संस्कार में शामिल होने आये श्याम बहादुर चौहान गोमती नदी में नहाने गये जो पानी के गहरे स्थान पर जाकर डूब गये थे। पुलिस सहित स्थानीय गोताखोरों ने उनकी बहुत खोजबीन की परन्तु कहीं पता नहीं चल पाया। उनके पुत्र आदित्य सहित अन्य साथी लगातर खोजबीन में लगे रहे। आखिरकार मंगलवार की सुबह उक्त गांव के पास श्याम बहादुर की लाश मिल गयी। इस बाबत पूछे जाने पर थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है।

# जनगणना आज से शुरू - 33 सवाल में घर की इनकम से लेकर पढ़ाई तक; क्या-क्या बताना होगा और क्या है जियो मैपिंग?

नई दिल्ली। देश में जनगणना की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। बुधवार यानी 1 अप्रैल से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इस बार जनगणना का तरीका पहले से काफी अलग होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और मकानों की गिनती में जियो-रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर घर की लोकेशन सीधे डिजिटल मैप पर दर्ज हो सके। सरकार की मानें तो इससे न तो कोई मकान छूटेगा और न ही किसी घर की गिनती दो बार होगी।

**कितने सालों बाद होगी जातिगत जनगणना?**

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी, यानी मकानों और घरों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा, जोकि फरवरी 2027 में शुरू होगा। एक और अहम बात। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति से जुड़ा डेटा भी जुटाया जाएगा। इससे पहले ऐसा 1931 की जनगणना में हुआ था।

**जनगणना 2027 की प्रक्रिया क्या है?**

इस बार लोगों को एक नया विकल्प भी दिया गया है, जिसका नाम है- सेल्फ एन्युमरेशन (स्व-गणना) यानी चाहें तो आप खुद भी अपने घर की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर जाना होगा।

प्रक्रिया ज्यादा जटिल नहीं है। पहले लॉगिन कर राज्य चुनना होगा और कैप्चा भरना होगा।

फिर घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके बाद 16 भाषाओं में से एक भाषा चुननी होगी और इलाके से वेरिफिकेशन करना होगा।

फिर जिला या शहर की जानकारी भरकर मैप पर दिख रहे लाल मार्कर को अपने घर की सही लोकेशन पर सेट करना होगा।

इसके बाद हाउस लिस्टिंग से जुड़े 33 सवालों के जवाब देने होंगे।

सभी जानकारी भरने के बाद डेटा का प्रीव्यू देखा जा सकेगा। संतुष्ट होने पर फाइनल सबमिट करना होगा।

सबमिट करते ही स्क्रीन पर SE ID दिखाई देगी। यही आईडी बाद में जनगणना कर्मी को दिखानी होगी ताकि आपका डेटा सत्यापित किया जा सके। इस प्रक्रिया में गौर करने वाली बात ये है- एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक घर रजिस्टर होगा और मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

**जनगणना कर्मियों को कौन-सा डेटा गोपनीय रखना होगा?**

जनगणना से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। डेटा को उसी स्तर की सुरक्षा दी जाएगी जो परमाणु ऊर्जा केंद्रों, नेशनल पावर ग्रिड या सैन्य नेटवर्क को दी जाती है। इसकी निगरानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के तहत होगी। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा और आरटीआई के दायरे से भी बाहर होगा।

# ईरान की खुली चेतावनी- कल से अमेरिकी कंपनियों पर करेंगे हमले; माइक्रोसॉफ्ट, एपल और टेस्ला समेत ये भी निशाने पर

तेहरान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को लेकर खुली चेतावनी दी है। ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अगर ईरानी नेताओं पर हमले जारी रहे, तो वह पश्चिम एशिया में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा। इस बयान से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और वैश्विक स्तर पर चिंता गहरा गई है। ईरान ने साफ कहा है कि 1 अप्रैल से तेहरान समय के अनुसार रात 8 बजे के बाद अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों पर हमले शुरू किए जा सकते हैं। भारत के समय के अनुसार यह रात 10:30 बजे होगा। ईरान ने कहा है कि हर हमले के बदले इन कंपनियों की यूनिट्स को तबाह किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को तुरंत अपने कार्यस्थलों से हटने की चेतावनी भी दी गई है।

**क्या अमेरिकी कंपनियां सीधे निशाने पर हैं?**

ईरान ने 15 बड़ी अमेरिकी कंपनियों की सूची जारी की है।

**कौन-कौन सी कंपनियां आईआरजीसी के निशाने पर हैं**

- माइक्रोसॉफ्ट
- गूगल
- एपल
- इंटेल
- आईबीएम (इंटरनेशनल बिजनेस मशीन)
- टेस्ला
- बोइंग
- डेल टेक्नोलॉजीज
- हेवलेट पैकार्ड (एचपी)
- सिस्को
- ओरेकल
- मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम)
- जेपी मॉर्गन चेस
- जनरल इलेक्ट्रिक
- हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज




इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, आईबीएम, टेस्ला और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

इसके अलावा डेल, एचपी, सिस्को, ओरेकल और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। इससे साफ है कि ईरान अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहना चाहता।

**क्या यह सिर्फ चेतावनी है या बड़ा खतरा?**

आईआरजीसी ने पहले भी ऐसी चेतावनियां दी हैं, लेकिन इस बार समय सीमा तय करने से खतरा ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह धमकी सच में लागू होती है, तो इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है। ईरान ने अपने बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां युद्ध में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका आरोप है कि ये कंपनियां अमेरिका को ऑपरेशन की योजना बनाने और हमले करने में मदद करती हैं। इसी वजह से इन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

**क्या कर्मचारियों के लिए खतरा बढ़ गया है?**

ईरान ने कंपनियों के कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे तुरंत अपने दफ्तर छोड़ दें। इससे साफ है कि खतरा सिर्फ कंपनियों के ढांचों तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा भी सवालों में है।

**क्या इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा?**

अगर इन कंपनियों पर हमला होता है, तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। ये सभी कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं। ऐसे में आईटी, टेक्नोलॉजी और व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इससे बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है और निवेशकों की चिंता भी बढ़ेगी। इस धमकी के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया अहम होगी। अगर जवाबी कार्रवाई होती है, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। साफ है कि मध्य पूर्व में तनाव अब नए स्तर पर पहुंच चुका है और आने वाले दिन बेहद संवेदनशील हो सकते हैं।

## सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त को फिर लिखा पत्र, बोलीं- बंगाल में फर्जी वोटरों से लोकतंत्र पर खतरा



कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है, जिससे असली वोटरों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा कि बंगाल में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग हजारों फर्जी फॉर्म-6 आवेदन जमा कर बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया वोटर हाईजैकिंग की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की रणनीति पहले महाराष्ट्र और दिल्ली में भी अपनाई गई थी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी भी 60 लाख से अधिक वास्तविक मतदाता जांच प्रक्रिया में फंसे हैं, जबकि बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन तेजी से स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के कारण अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसे उन्होंने बेहद चिंताजनक बताया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के बाद कोई नया नाम शामिल न किया जाए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने और इस कथित गड़बड़ी को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अपने लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगी।

## सूरत के घर में लगी भीषण आग, जिंदा जलकर 5 लोगों की मौत

गुजरात। गुजरात के सूरत शहर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के लिंबायत इलाके में एक तीन मंजिला मकान में आग लगने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चार महिलाएं और एक छोटा बच्चा शामिल है। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मीठी खाड़ी इलाके में हुआ। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस के अनुसार, जिस मकान में आग लगी वहां साड़ी पैकिंग का काम होता था। हादसे के समय परिवार के सदस्य फोम शीट की मदद से साड़ियों को पैक कर रहे थे। छुट्टी का दिन होने के कारण घर में पैकिंग का काफी सारा सामान और फोम जमा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे कमरे में काला धुआं भर गया। उप पुलिस आयुक्त कानन देसाई ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। कमरे के अंदर धुआं ही धुआं भरा था। लोग अंदर फंसे लोगों का दम घुटने लगा। गंभीर हालत में सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

## केरल में कांग्रेस का चुनाव प्रचार- राहुल गांधी बोले- सीपीएम अब वामपंथी नहीं

कन्नूर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी केरल के कन्नूर में रैली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह लड़ाई वाम मोर्चा (सीपीएम) की विचारधारा, यूडीएफ की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बीच है। पहली बार हम देख रहे हैं कि भाजपा और वाम मोर्चा के बीच गठबंधन हो रहा है। सामान्य तौर पर, किसी वामपंथी दल का किसी अति दक्षिणपंथी दल के साथ गठबंधन करना काफी आश्चर्यजनक होता। इसके साथ ही उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक (प्रधानमंत्री) केरल आते हैं, तो सबरीमाला के बारे में कुछ नहीं कहते।उन्होंने कहा भाजपा मुख्यमंत्री (पिनराई विजयन) का समर्थन कैसे कर रही है? पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, मंदिरों, धर्म और देवी-देवताओं की बात करते हैं। लेकिन जब वे केरल आते हैं, तो सबरीमाला मंदिर वाला मुद्दा नहीं उठाते। सीपीएम नेताओं ने सबरीमाला मंदिर से सोना चुराया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि केरल विधानसभा चुनाव में एलडीएफ की जीत हो। केरल में राहुल गांधी ने कहा कि सीपीआई (एम) अब वामपंथी पार्टी नहीं बल्कि अति दक्षिणपंथी पार्टी है।

**अदाणी का नाम लेकर साधा निशाना**

आगे उन्होंने कहा, अदाणी भाजपा की वित्तीय संरचना का आधार है। इसीलिए अमेरिका में अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, लेकिन यह मामला अदाणी को निशाना नहीं बना रहा है। यह मामला मोदी और भाजपा को निशाना बना रहा है।

## केरलम में बीजेपी का घोषणापत्र जारी, नितिन नबीन ने किया एम्स का वादा

कोलकाता।

केरलम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मंगलवार को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने केरल में एम्स बनाने और तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क विकसित करने का वादा किया है। घोषणापत्र में जरूरतमंद महिलाओं को 'भव्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड' देने का वादा किया गया है, जिसके तहत हर महीने 2500 दवाइयों और राशन के लिए दिए जाएंगे। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को 3000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। भाजपा ने इससे पहले असम के लिए भी मैनिफेस्टो (संकल्प पत्र) जारी किया। इसमें लव जिहाद पर एक्शन, घुसपैठियों से कब्जाई जमीन वापस लेने, राज्य में यूसीसी लागू करने, युवाओं को 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। पत्र में कुल 31 वादे किए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मैनिफेस्टो जारी होने पर कहा- आज हम यहां 'विकसित केरलम' का घोषणापत्र प्रस्तुत करने के लिए जमा हुए हैं। DF और LDF ने कभी भी केरलम के लोगों की प्रगति में रुचि नहीं दिखाई है। भाजपा ने केरल में गरीब परिवारों को हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है, जो ओणम और क्रिसमस के मौके पर मिलेंगे। साथ ही हर घर को हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने की बात कही गई है। इसके अलावा सबरीमाला और गुरुवायूर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए देवस्वम बोर्ड में सुधार करने की बात कही गई है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में तमिलनाडु को पानी और केरल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी वादा किया है।

## महावीर जयंती पर सीएम योगी ने दीं शुभकामनाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन जयंती की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा के शाश्वत सिद्धांतों से संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता के लिए अमर पाथेय हैं।

## निर्वाचन आयोग के कार्यालय के सामने टीएमसी-भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर मंगलवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। यहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थित बूथ-स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के बीच मतदाता सूची में कथित हेराफेरी को लेकर झड़प हुई। पुलिस को स्थिति को काबू में लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद फॉर्म 6 के कथित दुरुपयोग को लेकर विरोध प्रदर्शन भड़क गया। फॉर्म 6 का इस्तेमाल कथित तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे एनडीए शासित राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किया जा रहा था। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दखल दिया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस बीच, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि फॉर्म 6 के जरिये बाहरी राज्यों के मतदाताओं को बड़े पैमाने पर बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश कर रही है। सोमवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि भाजपा ने एक ही दिन में करीब 30 हजार फॉर्म 6 जमा किए थे, जिससे अन्य राज्यों के निवासियों को पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में दर्ज किया जा सके। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि विरोध के दौरान भाजपा समर्थकों ने उन पर हमला किया। पुलिस ने कहा कि कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नए कार्यालय के बाहर अतिरिक्त बल तैनात किए गए, ताकि इसे काबू किया जा सके। पुलिस ने कहा कि अधिकारी आगे हिंसा रोकने के लिए स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

**पुलिस को स्थिति को काबू में लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का दौरा किया।**

# नालंदा के मंदिर में भगदड़, 9 की मौत

**इनमें 8 महिलाएं; राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2500 जवान, 25 हजार श्रद्धालुओं के लिए कोई नहीं**

- **पीड़ित परिवार की सरकार हर तरह से मदद करेगी: मंत्री श्रवण कुमार**
- **गर्भ गृह में 20 लोगों से ज्यादा की जगह नहीं**

नालंदा। बिहार में नालंदा जिले में मंगलवार सुबह शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 8 महिलाओं की भीड़ में दबने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में दम तोड़ा। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। वहां मेला भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। दर्शन करने की जल्दी में धक्का-मुक्की मच गई। अफरातफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद मंदिर और मेला को बंद करवा दिया है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुईं। उनकी सुरक्षा में 8 जिलों के 2500 जवानों को लगाया गया था, जबकि मंदिर में जुटी 25 हजार की भीड़ के लिए एक भी पुलिस वाले की तैनाती नहीं थी। हादसे के बाद पटना कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया है। सीएम ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। दीपनगर थाने के SHO राजमणि को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है।

**40 मिनट बाद पहुंची एंबुलेंस**

मंदिर में मौजूद एक श्रद्धालु ने बताया, 'भगदड़ के बाद कई महिलाएं बेहोश पड़ी थीं। कुछ दर्द से चिल्ला रही थीं। लोगों ने पुलिस को खबर की। पहले 2-3 पुलिस वाले पहुंचे। उनके साथ मिलकर श्रद्धालुओं ने घायल महिलाओं को किनारे लिटाया। कई बार एंबुलेंस के लिए फोन किया गया। घटना के करीब 40 मिनट बाद पहली एंबुलेंस पहुंची और पुलिस के कुछ अफसर भी आए। इसके बाद घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। महिलाओं को उठाते समय ही लग रहा था कि उनमें से कुछ की मौत हो गई है।'

# घरों तक जंग की आंच, दूध-किराना-इलाज महंगे होंगे

**'रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ाने की तैयारी; कॉमर्शियल एलपीजी की कमी से हजारों प्लास्टिक यूनिट बंद**

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कंपनियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ रही है और कंपनियां दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। इससे बोतलबंद पानी, नमक, तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें, एसी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर नॉन-सर्जिकल मेडिकल आइटम के दाम बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि इस जंग ने प्लास्टिक उद्योग की रीढ़ तोड़ दी है। बीते 30 दिनों में कच्चे माल के दाम 50-70फीसदी तक बढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले प्लास्टिक दाने एलडीपीई के दाम 110 रु/ किलो से 180 रुपए तक पहुंच गए हैं। अन्य पॉलीमर और रॉ मटेरियल भी 30 हजार से 70 हजार रुपए प्रति टन तक वृद्धि हुई है। ऐसे में अप्रैल में प्लास्टिक की कीमतें 50-60फीसदी तक बढ़ सकती हैं। प्लास्टिक टंकी व कंटेनर के दाम 30-40फीसदी तक बढ़ने की आशंका है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील शाह कहते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री से 5 लाख लोग जुड़े हैं। संकट बढ़ा तो दो-तीन लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हमारी मांग है कि स्थिति सामान्य होने तक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर 18फीसदी जीएसटी को कम करके 5फीसदी तक लाया जाए। बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट 20फीसदी तक बढ़ा दें। इससे कैश फ्लो समस्या हल होगी।

**एलपीजी संकट से 20 हजार छोटे उद्योगों पर लगा ताला**

असर 50 हजार प्लास्टिक फैक्ट्रियों पर पड़ा है। कॉमर्शियल एलपीजी की कमी झेल रहे अधिकांश यूनिट्स ने उत्पादन बंद कर दिया या घटा दिया। करीब 20 हजार कारखाने बंद होने का अनुमान है। हैदराबाद के एक ईपीई निर्माता ने बताया, 'हम गैस के बिना उत्पादन नहीं कर सकते। 80 रुपए/किलो तो छोड़िए 150 में भी नहीं मिल रही।' गुजरात के राजकोट में 40 से ज्यादा प्लांट बंद हो चुके हैं। मध्यप्रदेश, रायपुर और हैदराबाद में भी कई प्लांट बंद हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माता लंबे समय तक मार्जिन का दबाव नहीं झेल पा रहे। कई यूनिट्स ने पुराने ऑर्डर रद्द कर दिए हैं।